भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3457
जिसका उत्तर मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

वाहनों की बिक्री में गिरावट

3457. डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहनों सहित अन्य प्रकार के वाहनों की बिक्री मे कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या बाजार में वाहनों की बिक्री की मांग में कमी के कारण कुछ डीलरों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को वाहनों की बिक्री पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से और कम करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या वाहन क्षेत्र को कर-संबंधी प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या अप्रैल, 2020 तक वाहनों को बीएस-4 से बीएस-6 स्तर में बदला जा रहा है और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री की मांग में कमी के कारणों में से यह भी एक कारण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऑटोमोबाइल उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (च): पिछले कुछ महीनों से ऑटोमोटिव क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में आवर्ती मंदी है। ऑटोमोबाइल की बिक्री में गिरावट के लिए पूर्वानुमान के साथ अनेक वित्तीय और विनियामक कारण हैं, जो निम्नानुसार हैं:

- ऑटो सेक्टर के लिए वित्त की उपलब्धता में कटौती।
- वाणिज्यिक वाहन के लिए एक्सल लोड सीमा में वृद्धि 25% तक विस्तारित माल ढुलाई क्षमता, जिससे नए वाहन की मांग में कमी आई है।
- 3 साल (नई कारों) और 5 साल (नए दुपहिया) के लिए दीर्घकालिक तीसरा पक्ष बीमा प्रीमियम के अग्रिम संग्रह के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण वाहन की लागत में वृद्धि।
- डीलरों के लिए 25% से 60% तक कोलेटरल में वृद्धि के परिणामस्वरूप डीलरों की इन्वेंट्री वित्त में कमी हुई।
- बीएस-IV मानदंडों (बीएस III से बीएस IV में परिवर्तन के समान स्थिति) के साथ स्टॉक क्लीयरिंग के लिए ओईएम द्वारा छूट की प्रत्याशा में खरीद को स्थगित करना।

फेडरेशन ऑफ डीलर एसोसिएशन (एफएडीए) द्वारा साझा की गई सुविधा के अनुसार, विभिन्न कारणों से विभिन्न ओईएम से संबंधित कुल 286 डीलरशिप बंद की गई हैं।

जब कभी आवश्यक होता है, सरकार एक नीति निर्माता के रूप में हमेशा ऑटो सेक्टर के व्यापक और सतत विकास के लिए अनेक उपायों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने एवं इसमें सुधार करने का प्रयास करती है। ऑटो में उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:

- कॉरपोरेट टैक्स में 22% तक की कटौती
- भविष्य में आईसीई और ईवी के पंजीकरण की निरंतरता
- परिमार्जन नीति पर विचार किया जा रहा है।
- जून 2020 तक स्थगित नई कारों के पंजीकरण में प्रस्तावित वृद्धि
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैंकों को ₹70,000 करोड़ जारी किए गए।
- खरीदे गए वाहन के लिए रेपो दर को ब्याज से जोड़ना।

*****